[Shri J. B. Patnaik]

complaint in accordance with the regulations made in this Act"

Then it says that:

"The regulation referred to in sub-section (1) shall provide for the complaint to be forwarded to the Central Government for its consideration if the complainant is not satisfied with the decision on his complaint"

So the provision is already there for making a complaint against any decision given by a superior officer and the Central Government is empowered to take a decision in this regard and redress the grievances of the officer The grievances of officers in all the services are being redressed under this process.

In regard to the general emoluments of the armed forces, certain observations have been made It is said that the armed forces are discontented as a result of the recommendations of the Pay Commission I would like to say that there is absolutely no discontent as far as the Government's improvement on the recommendations of the Pay Commission goes.

SHRI P. K. DEO: Question.

SHRI J. B. PATNAIK: Improvements have already been made in the pay scales of officers. As far the pay scales of the jawans, this has earlier been done. I have never heard of any discontent anywhere and we should not import discontent into our highly disciplined and contented armed forces

As regards the case of a Judge Advocate General made out by my hon. friend, I do not know the particulars of this case I would certainly look into it, but the amendment has nothing to do with it The amendment is a simple one; it is just in order to provide a facility for the officers serving in the Navy who are denied this facility .

With these words, I move.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That the Bill, as amended, be passed."

The motion was adopted

15.26 hrs.

INDIAN WORKS OF DEFENCE (AMENDMENT) BILL

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI J. B. PATNAIK): Sir, I beg to move:

"That the Bill further to amend the Indian Works of Defence Act, 1903, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration."

This amendment again is a very simple one. The Act came into force in March, 1903 The purpose of the Act was to keep our works of defence and the assets as safe and secure as possible For this purpose, certain restrictions were imposed on the use of lands adjacent to the works of defence The Act also provided for determining the amount of compensation to be paid for the removal of such buildings or constructions around or adjacent to any works of defence and to provide a machinery for this purpose. The machinery to enforce the provisions of the Act has been specified under section 37 of the Act. Under this section, it is usually the Collector or an officer authorised for this, who has to enforce the provisions of this section. If in enforcing the provisions of this section, the Collector or the officer authorised is impeded in his duty, then he is empowered to enforce compliance for this purpose. If he is himself a magistrate, he can enforce compliance, having the magisterial power. If he is not, he will have to apply to a magistrate and in certain places like Calcutta, Madras and Bombay, the police commissioners have been empowered with the magisterial powers. So, in these three cities, the Collector has to apply for

compliance with the provisions to the police commissioners.

There are some places where the post of Police commissioners have been created. For example, at Nagpur and Poona. To provide for this in the Act, the amendment is brought before the House to the effect that the Collector has to apply to the police recommissioners wherever such posts are created.

The Government has taken advantage, taking this opportunity, to bring forward two minor amendments to the Act. The first is to the short title of the principal Act, namely, the Indian Works of Defence Act. Now, this prefix "Indian" is not given to any of our Acts, and we have taken this opportunity to remove this prefix from the name of the Act It would be simply the "Works of Defence Act, 1903."

According to section 44 of this At, the Central Government is authorised to make rules for the guidance of officers in all matters connected with the enforcement of this Act Now, all such rules have to be placed before both Houses of Parliament, and hence we have made a provision to this effect.

With these words, I move.

MR. DEPUTY SPEAKER: Where is the amendment by which you seek to remove the word "Indian?"

AN HON. MEMEBEI: It is there.

MR. DEPUTY SPEAKER: One Minute. This Bill, as passed by the Rajya Sabha, says in clause 1:

> "This Act may be called the Indian Works of Defence (Amendment) Act, 1973."

You said that you had taken the opportunity of removing the word 'Indian'. I do not see it anywhere here.

The purpose of the Bill as far as I see is that besides the Commissioners of Police of Calcutta, Madras and Bombay, the Commissioners of police in other cities as may be appointed will also be empowered to enforce the provisions.

श्री मोहम्मद इस्माइल (बैरकपुर) : डिप्टी स्पीकर साहब, इण्डियन वर्क्स आफ डिफेन्स के सिलसिले में जो बिल पेश किया गया है, मुझे इस में कोई खास इख्तिलाफ नहीं है, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि यह एक्ट 1903 का है। ब्रिटिश हुकमत ने इस कानून को बनाया था, बीच बीच में जरूरत पड़ने पर इस में अमेण्डमेन्ट्स होते गये और इस वक्त भी अमेण्डमेन्ट ही पेश किया गया है। मैं सरकार से यह उम्मीद करता था कि इस तरह के पीस-मील अमेण्डमेन्ट्स न ला कर वह कोई काम्प्रीहैन्सिव बिल लाती और इस कानून में मौजूदा जमाने के लिहाज से तबदीलियां करती।

दूसरी बात—इस अमेण्डमेन्ट बिल को लाने की बात आप के दिमाग में तब उठी, जब मुल्क में और इस पार्लियामेन्ट में मारुति का सवाल उठा। यह सवाल इतने जोरों से उठा कि शुक्ला जी उस का जवाब न दे पाये, पूरी कैबिनेट भी उस का जवाब नहीं दे सकी, आप उस को डिफेण्ड नहीं कर सके। बड़ी बड़ी साजिशें इस के अन्दर चलीं। जो जमीन डिफेन्स के महकमे के तेहत थी उस को नाजायज तौर पर मारुति कम्पनी को दिया गया। जब उस की छानबीन शुरू हुई तब आप इस अमेण्डमेन्ट को लेकर यहां आये।

MR. DEPUTY-SPEAKER: This question came up so many times. It is not within the scope of the Bill. The scope is only to empower Commissioners of Police besides those of Calcutta, Madras and Bombay to en-

[Mr Deputy Speaker]

force the restrictions Why go into that case which has figured in this House again and again?

श्री मौहम्मद इस्माइल : जहा तक कलकत्ता का सावल है—मेरा तजुर्बा यह है कि मेरी अपनी कास्टीचूएन्सी मे डिफेन्स का बहुत बडा इलाका है—इच्छापुर मे लेकर दमदम तक फला हुआ है, जिस मे डिफेन्स की फैक्ट्रीज है । उस इलाके मे डिफेन्स की इस जमीन पर सैकडो-हजारो मकान बन गये है लोग किराये वसूल कर रहे है, लेकिन यह भी पता नही है कि उस जमीन का कौन मालिक है । जब जगजीवन राम जी डिफेन्स विभाग मे थे तो मैने उन से पूछा था कि ये जमीने किस की है । अगर ये जमीने हमारी है ता इन पर मकान कैसे बन गये । तब उन्होने एक कानून लाग किया—बगाल का जो रेन्ट कन्ट्रोल एक्ट था उस के मातहत उस को लाये । इतने दिनो से लूट मच रही थी लेकिन कोई देखने वाला नही था ।

बनहगली मे पचासो बीघे जमीन है । जब मैं वहा जाता तो लोग पूछते है । म्युनिस्पिल कमेटी नालिया बनाती है लेकिन यही मालूम नही कि वह जमीन किस की है । स्टेट गवर्नमेंट से पूछते है तो वे कहते है कि हमारे रिकार्ड मे नही है । डिफेन्स वालो से पूछो तो व कहते है कि हमारे पास तो रिकार्ड नही है, दिल्ली रेफर कर रहे है । वहा डण्ड-बठके लगती है गण्डे राज करते है । यह डिफेन्स की जमीनो की हालत है, एक्ट होने हुए भी आपने कुछ नही किया ।

कैन्टोनमेन्ट एक्ट के तहत जो उन के आसपास के इलाके है उन पर ऐसी पाबन्दियां आप ने लगा दी है कि लोग परेशान हो गये हैं। मैं यह जिक्र इसलिये यहा कर रहा हूं कि ये चीजें मे आप की नजर मे लाना चाहता हू । अमेण्डमेन्ट आप चाहे जो भी लायें है, लेकिन आप को यह देखना चाहिये कि अंग्रेजो के जमाने मे आप के पास कितनी जमीन थी, कहा कहा थी उस का पता लगाइये और अपने कब्जे मे लीजिये । अगर आप के पास फालतू जमीन पडी है तो उस को किसान को दे दीजिये ताकि वह अनाज पैदा कर सके । गरीबो को बांट दीजिये ताकि वह अपने लिये मकान बना ले । यह नही होना चाहिये कि दूसरे उस जमीन को तकसीम करे, आप के यहा अण्डर-ग्राउण्ड इस तरह से चल रहा है और आप के अफसरान लाखो रुपया इस तरह से लूट रहे है । मैं चाहता हू कि इस की जाच कराई जाय । एन्कवायरी करा कर आप उस रिपोर्ट को सदन के सामने रखे ताकि सदन को पता चल सके कि आप ने क्या कार्यवाही की है ।

तीसरी बात—आज डिफेन्स डिपार्टमेन्ट म करप्शन का बोलबाला है, इतना करप्शन आप कही नही सुनेंगे । आप के यहा मिलिट्री रूल है, बडा डिसिप्लिन है लेकिन फिर भी लाखो रुपये का माल गायब हो जाता है और कोई कुछ नही कर सकता । बाहर का तो कोई इन्टरफीअर कर ही नही सकता दूसरी जगह पुलिस तो जा सकती है, लेकिन यहा तो उस का भी दखल नही है—दिन-दहाडे ये सब कत्म होते है इच्छापुर फैक्ट्री मे गाडी-की गाडी पीतल की चली जाती है, कोई बोलनेवाला नही है—यह अन्धेर नगरी चौपट राजा नही तो क्या है ? अगर किसी एम्पलाई ने कम्पलेट कर दिया तो दूसरे दिन उस को सस्पैण्ड कर दिया जाता है, तुम ने क्यो इन्टरफीअर किया ? मैं जब से एम०पी० हुआ हू, मैने बहुत सी चीजे शुक्ला साहब को लिख कर भेजी हैं । अब आप आये है, आप को भी भेजूगा, देखना है कि आप क्या करते है ।

इस तरह की धाधली डिफेन्स के एम्प्लाइज के साथ हो रही है । इतना ही नहीं, वहां जो सामान बनता है, उस में बहुत

सी चीजें बिड़ला के लिये ईयरमार्क कर दी गई हैं, ये पुर्जे बिड़ला की फैक्टरी में बनेंगे। हमारे बड़े अच्छे अच्छे नौजवान लड़के वहां काम कर रहे हैं, नई चीजें ईजाद करते हैं, उन को उठा कर ट्रांस्फर कर दिया जाता है, हैदराबाद भेज देते हैं, नौकरी करनी है तो वहां जाओ। मैं ये बातें यहां पर आप की आगाही के लिये अर्ज कर रहा हूं।

जहां तक इन की सर्विस कण्डीशन्ज का सावल है, जो प्रोडक्शन होती है, चोरियां होती हैं, करप्शन होती है, इस को रोकने का सवाल है—मैं मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि ये लोग किस तरह से दिलचस्पी लें। आप चूंकि नये आये हैं, मझे उम्मीद है कि आप कुछ कर के दिखलायेंगे। लेकिन जो कुछ करें उस को सदन में भी पेश करें। ऐसा न हो जैसा तुलमोहन राम के मामले में हुआ, वैसी धांधली यहां न होने पाये। सीधे-सीधे तहकीकात करें और उस को देश के सामने रखें ताकि हम लोगों को भी मालूम हो सके और हम अपने क्षेत्र में जनता को बतला सकें कि उन मामलों पर तहकीकात हो रही है, विचार हो रहा है।

SHRI S. M. BANERJEE (Kanpur): Sir, while supporting the Bill I fully associate myself with the sentiments expressed by my hon. friend, Shri Mohd. Ismail. I come from Kanpur where also there is a cantonment with four defence factories and other defence units with nearly 35,000 employees. It is a fact that some plot of land is just taken over by the Defence Ministry or some defence department without any purpose. I can understand that the security has to be maintained but in the name of security, if large tracts of areas taken over by the defence department, which could be profitably used for cultivation and other purposes, it is not proper. This matter was brought to the notice of the Government in 1958 by a non-official resolution and at that time Shri Majithia, the then Deputy Defence Minister, assured the House that a comprehensive legislation is likely to be brought in soon which will amend those provisions in the existing Cantonments Act. I am told that a committee was appointed recently by Shri Jagjivan Ram, the then Defence Minister, with Shri Dave as Chairman and that he has submitted his report. I want to know what has happened to that report.

Are we really amending the existing Cantonments Act which was enacted by the Britishers? It was the idea of the British that the army should not be kept in touch with the people. So, they kept them separate. Today the army consists of the children of the soil, the brave sons of the peasants, workers and middle class employees of our country.

So, they should not be kept in isolation. Also what is the use of keeping so much of land idle when it could otherwise be profitably used?

Certain instances have been brought to our notice where some buildings which have been put up in those lands, either in the form of jhuggies or jompries or small cottages, they are demolished. This happened in Jubbalpur not long ago. Hundreds of people who have lived in those lands for the last 20 to 30 years suddenly received notice one day that their houses or cottages were likely to be demolished. Thanks to the intervention of the hon. Minister of State in the Defence Ministry, Shri Shukla, and also the then Defence Minister, Shri Jagjivan Ram, those cottages are still there and they will be regularised.

Why should this depend on the Military Estates Officer or the Director of Lands and Buildings? It can be done on the basis of the report of some officer in the Cantonment Board. So I would request, the hon. Minister to go through the various provisions in the Cantonments Act also along with this. We do not mind passing this legislation, if it is required, but the time has

[Shri S M. Banerjee]

come when the entire complexion of the cantonments will have to be changed Because, we cannot possibly afford to have more land at the disposal of the defence units than is absolutely necessary when we have a large number of peasants and landless labour After all we canot stretch our land, land cannot expand, it can only shrink So, distribution of this land has to take place among the landless labour

Then, everybody has to tighten his belt and specially, the Defence Ministry has also to sacrifice in the interest of the country I do not say that they are not doing it They are doing it They are laying down their lives for the sake of the country

You take any Defence project any ordnance factory at Ambajhari and at other places I have been told that a huge area of land is lying at the disposal of the Defence Ministry Let them put up farms there Let the Defence Department start farms there When there is a tremandous shortage of food in the country, when the people are dying of starvation how can we afford to have so much of land in the name of the security of a particular Defence project? This is a sad commentary on socialism and the talk of giving land to landless labour

Another point is as my hon friend Shri Mohammad Ismail said there are no quarters for the Defence employees working in the Ordnance Depots You take all the Ordnance Depots throughout the country whether in Delhi Cant or in Kanpur or anywhere else The quarters are available only to the 50 per cent of the employees of the Ordnance factories There is the M E S They are supposed to build quarters for everyone Naturally you cannot expect efficiency from the Defence employees if they know that their address is only "C/o footpath" I would request the hon Minister to do something about it

I would urge upon the hon Minister to assure the House that a comprehensive Bill be brought forward by the Government which will change the complexion of all the Defence projects and the surplus land available with the Defence Ministry either in the form of a project or an ordnance factory or a depot will be made available for cultivation purposes, for constructing quarters and so on.

I can understand about an ammunition factory that you cannot possibly construct anything within a range of 5-6 miles of the ammunition factory But about those factories which are not ammunition factories there at least you could do it I would request the hon Minister to go to the Panagarh depot and see that a stretch of land, kilometre after kilometre is there which has become a dumping ground Where the surplus land is available it should be given to the peasants

With these words I would request the hon Minister to throw some light on these matters Let the hon Minister assure us that he will apply his mind to these things The whole difficulty is that by the time anybody is able to apply his mind honestly intelligently and objectively on a paticular subject he is transferred to another Ministry This reshuffling has become the order of the day I do not know when she is going to stop the reshuffling every year every six months When a Minister understands that the word is not 'Ordinance" but Ordnance' he is shifted to another Ministry I am saying from my own experience (*Interruptions*)

This is a harmless Bill I support it I have spent the ambitious period of my life about 20 years in the Ordnance Depot The hon Minister is more educated than me I would request him to consider the suggestions made by me

श्री राम रतन शर्मा (बांदा) इंडियन वर्क्स आफ डिफेंस एमेंडमेंट बिल 1973 के बारे में मंत्री जी का कहना है कि यह बहुत छोटा सा बिल है । इस पर मुझ एक कहानी याद

आ गई । एक आदमी बाजार मे दो उल्लू बेच रहा था, एक बड़ा था और दूसरा छोटा उल्लू था । एक आदमी खरीदने पहुचा । उसने कहा कि बडे उल्लू की क्या कीमत है, उसने पाच रुपये बताई । जब उसने छोटे उल्लू की कीमत पूछी उसने दस रुपये बताई । खरीदने वाले को बडा ताज्जुब हुआ । उसने कारण पूछा तो उसने बताया कि बडा उल्लू खाली उल्लू है जबकि छोटा उल्लू उल्लू का पट्ठा है, इसलिए इसकी कीमत ज्यादा है । मत्री जी ने बडे इन्नोसेंट शब्दो मे कहा है कि यह बहुत छोटा सा बिल है । मैं अपने पूर्व वक्ताओ से इस बात मे सहमत हू कि उनको एक कम्प्रिहैंसिव बिल लाना चाहिये और देश की सुरक्षा के साथ कोई खिलवाड न कर सके इसको देखना चाहिये ।

1903 का यह एक्ट है । इस एक्ट के तहत डिफेन्स प्रोडक्शन और फैक्ट्रीज के आसपास की जमीन पर कोई अनआथोराइज्ड आक्युपेशन न हो इसके लिए इस मे सेफगार्डज रखे गए है जब से स्वतत्रता मिली और आप शासन मे आए तब से मै जानना चाहता हू कि इस एक्ट के तहत आपने कितने केसिस चलाए है कितनी ऐसी जमीन पर और किन लोगो द्वारा अनआथोराइज्ड आक्युपेशन किया गया है और कितनी उस म से आपने छुडाई है िनैक्टर्ज ने कितने केसिस मे एक्शन लिया है । जब देश की प्रधान मत्री मारुति कार के लिए डिफेन्स की जमीन पर अतिक्रमण कर सकती है, जब देश के मुख्य मत्री और मत्रीगण ऐसा कर सकते है तब आप क्या यह समझते है कि साधारण को अधिकारीगण है तथा दूसरे जो भी पावर मे है वे इस तरह के काम नही करेगे ? कानून आप सुबह से शाम तक बनाते हैं लेकिन उन प अमल नही होता है । अमल ही महत्त्पूर्ण है । कानून बनाना महत्वपूर्ण नही है । कानूनो का संरक्षण करना, उन पर चलना महत्वपूर्ण है । मुझे दुख है कि आप कानून के हिसाब से नही चलते है । उसके हिसाब से आचरण नही करते हैं । आप अपनी आचरण सुधार ।

आप पीसमील लेजिस्लेशन ला रहे है । आप ने चाहे सही या गलती से कहा कि आप इडियन वर्ड को हटाना चाहते है, इडियन वर्क्स आफ डिफेंस मे इडियन को ओमिट आप करना चाहते है । 1903 के एक्ट मे जो डेफीनीशन क्लाज है उसको आप पढे । सेक्शन 2 को पढे । उस मे कई चीजे आपको ऐसी मिलेगी जिन मे सुधार होना चाहिये । मै उदाहरण देता हू । एंटाइटल्ड टू एक्ट को आप देखे ।

> "The following persons shall be deemed 'entitled to act' as and to the extent hereinafter provided, that is to say—
>
> A married woman, in eases to which the English law is applicable, shall be deemed the person so entitled to act and whether of full ᵃge or not to the same extent as if she were unmarried and of full age"

SHRI J B PATNAIK That has already been amended by the Amending Act of 1965

श्री राम रतन शर्मा I am coming to that You have amended in 1965

वह एमेंडमेंट किया । फिर इसको रखा क्यो ? 1965 मे ये सब चीजे क्यो नही की इसको भी तब खत्म क्यो नही किया । अब 1974 मे क्यो कर रहे हे । इसको भी आपने रखा। उसको भी रखा । लायर्ज पैरेडाइज आप कानूनो को क्या बनाते है । ऐसे कानून बनाए जो साधारण जनता की समझ मे आ सके । प्रोवाइडिड, प्रोवाइडिड जितने ही पास जोड देते है । इसकी क्या जरूरत है । 1965 मे जो एमेंडमेंट आपने किया वह अपनी जगह पर ठीक है । मैंने उसको देखा है । उसके बारे मे मेरी आलोचना नही है । मेरा कहना यह है कि

[श्री राम रतन शर्मा]

पूरे लजिस्लेशन को आप एक बार पढ़, और जो चीजें आज की कंडिशन मे फिट इन नही होती है उनको आप निकाले या बदले और एक कम्प्रिहैंसिव बिल इस सिलसिले मे लाए । 1965 मे इन्होने जो एमेंडमेंट किया 2(ए) एक्ट 39 आफ 1965 के हिसाब से उसी समय आप सब कर सकते थे । उसकी तरफ आपने आज तक ध्यान नही दिया । और सब से बडी बात यह है कि आज तक जितने केसिस एनक्रोचमेंट के हुए है, दूसरो से उस जमीन पर कब्जा करवाया गया है, दूसरो को बाटा गया है उस सब के क्या दूरगामी परिणाम होगे इसको देखा जाए ।

अन्त मे मै पुन: आग्रह करता हू कि इन सब चीजो को देख कर एक कम्प्रिहैंसिव बिल लाया जाए ताकि जनता को राहत मिल सके और जनता की अच्छी तरह से रक्षा हो सके और डिफेंस की भी रक्षा हो सके ।

*SHRI J MATHA GOWDER (Nilgiris) Mr Deputy Speaker, Sir, I rise to say a few words on the Indian Works of Defence (Amendment) Bill As the hon Minister pointed out in his introductory remarks this is no doubt a small piece of legislation But, the problems being faced by the common people as a result of implementation of the parent Act are manifold

Initially, I would refer to Clause 4 of the Bill which provides the Government with the powers to formulate rules under this Act and also to place such rules on the table of both the Houses of Parliament I have to say that there is firstly inordinate delay in framing rules not only under this Act but also under many other Acts If after many months of enactment of a legislation the rules are framed, there is every chance of exceeding the powers granted to the Government under the provisions of the Act We have the most important committee called the Subordinate Legislation Committee which examines thoroughly the rules to find out whether there has been any excess committed by the Government in delegating the powers under the rules As we normally see every day, there is also unconscionable delay in laying such rules on the table of this House. In consequence the Subordinate Legislation Committee cannot function effectively and purposefully. By the time the Subordinate Legislation Committee examines this question and submits its report to the House, the Government would have gone on implementing the rules and regulations, however defective or excessive they might be in comparison with the provisions of the parent Act

I would like to request the hon Minister to ensure that the rules are framed expeditiously and placed on the table of both the Houses of Parliament without undue delay They only the question of delegated legislation will have its significance in our democratic system.

16 00 hrs

Sir, in my Constitutency, the Nilgiris there is Willingdon Cantonment, where many civilians are living I regret to point that the Cantonment Board has not provided to them even the minimum basic amenities for living to these civilians I have taken up this issue many times with the Cantonment Board authorities They take great care and caution in meeting the requirements of their own Officers living there and the civilians are left to fend for themselves I am sure that this must be the fate of civilians in almost all the Cantonment areas in many parts of our country I request through you the hon Minister to look into this human problem and do the needful immediately

Similarly, in the Cantonment area of Willingdon, vast tracts of land had been taken on 99-years lease from the villagers by the Britishers. Now the 99-year lease period is over The lands

*The original speech was delivered in Tamil.

have not been purchased outright from the villagers, they were getting all these years only lease charges. The villagers have been repeatedly pleading with the authorities that the lands must be returned to them because the 99-year lease period is over. If that is not possible they should be given alternative land outside the Cantonment area. If that is also not feasible, they should at least get adequate compensation for the land which has been taken from them on 99-year lease only But all their pleas have fallen on the statue-like Cantonment Board which remains unmoved I appeal to the hon Minister that he should bestow his personal attention in solving this human problem I would even go to the extent of saying that the lands which remain unutilised by the Cantonment Board could easily be cultivated by the local people, after all they are the citizens of this country they are not going to manufacture bombs in such areas They will naturally contribute something to the nation's growing requirement of foodgrains We are passing through such hard times that every inch of cultivable land, whether it is within the Cantonment area or not, should be utilised for producing foodgrains If the Cantonment authorities cannot trust the local people let them do cultivation themselves and produce foodgrains We cannot afford to allow such vast tracts to go waste I hope that the Government will ponder over this problem in all seriousness

There is another important issue in my constituency, The Nilgiris There is Aravangod Cardite Factory which was set up by the Britishers They chose this area for producing gunpowder etc because of the salubrious climate in this area There is vast area available for expanding this factory. Instead of expanding this factory, the Government, I regret to point out are shifting in parts this factory to the northern parts of our country I do not know the reasons for taking away this landmark in my constituency I would appeal to the hon Minister that he should stop this process of shifting this factory to other places. It should be expanded further in Aravangod itself The Government should not deprive the backward area like my constituency by taking away this factory to some other place, this will further reduce the dwindling job opportunities in this area. I appeal to the hon. Minister that the Government should formulate a comprehensive land policy in the Cantonment areas of the country.

श्री नाथूराम अहिरवार (टीकमगढ़) उपाध्यक्ष महोदय, जो संशोधन प्रस्तुत किया गया है, मै उसका समर्थन तो करता हू, लेकिन मैं इस बारे मे कुछ सुझाव देना चाहता हू ।

मेरे क्षेत्र मे झासी और बबीना दो कैन्टोनमेट बोर्ड है । जब बबीना कैन्टोनमेट बोर्ड बना, तो 17, 18 गावो को हटा दिया गया और वहा के किसानो की जमीन ले ली गई, बहुत से किसान गाव छोडकर चले गये । लेकिन वह जमीन आज भी खाली पडी हुई है । मिलिटरी की तरफ से न उसका कोई उपयोग होता है और न ही कोई खेती होती है । किसानो को अपनी जमीन के बदले मे न जमीन मिली है और न मुआवजा मिला है ।

झासी कैन्टोनमेट बोर्ड बहुत पुराना है । वहा की इमारते 1914 से पहले की बनी हुई है । इस समय ऐसा कानून है कि अगर किसी आदमी की खपरैल गिर भी जाये तो वह दूसरी खपरैल नही बना सकता है । बाहर तो लोग लीपा पोत कर अच्छे औपड़ बना लेते हैं लेकिन वह खपरैल भी ठीक नही कर सकता है । छत डालना तो दूर की बात है । कैन्टोनमेट एक्ट बहुत पुराना है और उसमे संशोधन करना आवश्यक है ।

कैन्टोनमेट एरिया मे मिलिटरी पर्सोनल के लिये तीन तीन मन्जिला मकान बनाये जाते है ? तो फिर बस्ती मे रहने वाले लोग क्यो नही अच्छे मकान बना सकते हैं ? वहा पुराने टाइप की लैट्रिन्ज बनी हुई हैं,बडी गन्दी नालियां है और सफाई का कोई इन्तजाम नही है । ऐसी हालत मे बस्ती मे से गुजरना

[श्री नाथू राम अहिरवार]

मुश्किल होता है और वहा बीमारियां भी बढ़ती हैं ।

कैन्टोनमेंट बोर्ड के दो सदस्य वहा के एक्जीक्यूटिव आफिसर से मिलने के लिये गये, जो कि एक कर्नल है । उस कर्नल ने उनको कहा कि ठीक खड़े रहो, मैं यहा का कर्नल हू, मैं तुम्हे बाहर निकाल दूगा । उसने जनता के चुने हुये मेम्बरो को धक्का देकर बाहर निकाल दिया । मैंने इस बारे मे लिखकर शिकायत भेजी है ।

झांसी कैन्टोनमेंट की बहुत बुरी हालत है । वहा पुराने मकान और बगले है, जो बहुत बुरी हालत मे है । अगर वहा मकान बनाने की इजाजत नही दी जा सकती है, तो म्यूनिसिपैलिटी को दे दीजिये । मकानो को नीलाम करने और लीज पर देने की बात कही जाती है । मेरा निवेदन है कि इनने पुराने कैन्टोनमेंट एक्ट के स्थान पर नया कानून बनाया जाये, ताकि अच्छे मकान बन सकें और स्वास्थ्य-सेवाओं की व्यवस्था की जा सके ।

श्री जनेश्वर मिश्र (इलाहाबाद) उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल को देखने के बाद और मंत्री महोदय का भाषण सुनने के बाद मै अभी भी इस राय का हू कि अगर यह बिल पास कर दिया जाये तो वह इस लिये निरर्थक हो जायेगा कि डिफेंस की जगह के बगल मे जो बडे लोग अपनी इमारते बना लेते है या कारखाने खुलवा लेते है उन लोगो की इमारतो और कारखानो को हटाने की क्षमता इस सरकार मे नही है । इस स्थिति मे यह बिल बेमतलब है । बिल की भाषा शक्तिशाली है, लेकिन इसका मतलब तभी सिद्ध हो सकता है, जबकि इसके द्वारा इस प्रकार के निर्माण को रोका जा सके ।

कई पूर्ववक्ताओ ने मारुति कारखाने का जिक्र किया है । पालम हवाई अड्डे के बगल मे डिफेंस आफिशल्ज ने उस पर आपत्ति की, लेकिन हरियाणा के मुख्य मंत्री ने वह जमीन मारुति कारखाने खोलने के लिये दे दी । अगर मंत्री महोदय इस बिल के पास हो जाने के बाद वह कारखाना रुकवा देंगे, तब तो इस बिल का कोई मतलब है । जो गरीब हरिजन, धोबी, नाई और भंगी आदि मिलिटरी के लोगो की सेवा करते हैं, और कैन्टोनमेंट बोर्ड के बगल मे सदर बाजार के नाम पर बसा करते हैं, अगर मंत्री महोदय इस बिल के द्वारा उनकी झोंपडियो को गिराने का अधिकार चाहते हैं, तो हम समझते हैं कि इस बिल का कोई मतलब नही है ।

कही न कही तो आप की सरहद होगी न । डिफेंस की जमीन होगी और उसके बाद सिविल लोगो की जमीन होगी । बीच मे कही सरहद बनेगी । आम तौर से जहा कही डिफेंस आफिशल्ज रहते है, वहा उसके बगल मे जो मुहल्ले बना करते है, हमने देखा है कि उत्तर प्रदेश मे और अन्य कई जगह उनका सदर बाजार कहते है । एक तरफ तो डिफेंस के कर्मचारियो और अधिकारियो के लिये आप बढ़िया इमारतें बनते हैं । उन के दरवाजे पर तोप खडी कर देते है और गुलदस्ते सजाते है और दूसरी तरफ सदर बाजार के नाम पर जो बस्तिया बनी रहती है जहा उन अधिकारियो के कपडे धोने वाले, उनके पाखाने साफ करने वाले और उनके यहा झाड लगाने वाले लोग रहते है, उन बस्तियो मे पाखाने बदबूदार होते है और सडक ऊबड-खाबड और टूटी हुई होती है । कैन्टोनमेंट की तरफ मे इस बारे मे कोई इन्तजाम नही होता है और डिफेंस भी उसको कभी नही देखता है । आखिर डिफेंस की जमीन हिन्दुस्तान के बाहर की जमीन नही होगी—वह इसी मुल्क की जमीन होगी । सरहद के बगल मे जो आम जनता रहती है वह आपके तहत होती है, या किसी सिविल अधिकारी के तहत नही होती है । इसलिये इस बिल मे उन लोगो के लिये सडको और सफाई आदि का इन्तजाम करने की गारटी देनी चाहिए ।

जीसरी बात-इनके पास बहुत जमीनें होती हैं। मैंने कई जगह देखा है। कई हवाई हड्डे देखें हैं। इलाहाबाद में देखा है। अंग्रेजी जमाने के हवाई अड्डे हैं। जमीनें पड़ी हुई हैं। आज तक उन पर कोई काम नहीं हुआ। एक इरादतगंज में हवाई अड्डा है। अभी जब पाकिस्तान से बंगला देश वाले शरणार्थी आये थे तो महीने डेढ़ महीने के लिये उन्हें ठहराया गया था वरना 27 साल से वह जमीन वैरन पड़ी हुई है। उसका कोई मतलब डिफेंस से है नहीं, कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन उसको फंसा कर रखना चाहते हैं। लोग मांग करते हैं कि आप दे दीजिये, हरिजन हैं, गरीब हैं या आपके ही मुहकमे के बहुत से लोग होंगे जो नौकरी करते होंगे, उनके घरों पर जमीन नहीं होगी, उन के रिश्ते दारों को दे दीजिये, वे खेती करें। लेकिन आप देते नहीं हैं। किस लिये वह जमीन रखे हुये हैं? आज देश में खाने का ठिकाना नहीं है। हिन्दुस्तान की सरकार दौड़ दौड़ कर विदेशों में गल्ला भीख मांगने के लिये जाती है। दूसरी तरफ विदेशों से लड़ने के लिये जो मिलिटरी रखी जाए उसके लिये इतनी फालतू जमीन रखी जाये, मैं समझता हूं कि यह बहुत अच्छा सिम्पटम हिन्दुस्तान के लिये नहीं है। इसलिये मैं आग्रह करूंगा कि ऐसी जितनी भी डिफेंस की जगह हैं जिनका कोई इस्तेमाल पिछले पांच सात साल से नहीं हो रहा है और आपके अधिकारी यह रिपोर्ट दे सकते हैं कि आने वाले दस सालों तक इस जमीन की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी इस तरह की जमीनें उन लोगों के बीच में जो हरिजन हैं, भूमिहीन हैं या आपके डिफेंस के ही गरीब एम्प्लाइज हैं उनके रिश्तेदार हैं, उनमें बंटवा दीजिये। आपके ही डिफेंस के बहुत से एम्प्लाई जो लड़ाई में मारे गये हैं उनकी विधवाएं हैं, उनकी मां हैं, उनके बूढ़े बाप हैं उनमें बंटवा दीजिये। उससे पैदावार करके वे अपने रोजी रोटी चलायें।

चौथी बात-कई जगहों पर मैंने देखा है कि जहां डिफेंस की जमीन है डिफेंस के लोग अड़ जाते हैं, सड़क बनी हुई है, मुश्किल से एक फर्लांग के आगे पी डब्लू डी की सड़क चलती है केवल एक फर्लांग के लिये डिफेंस की जमीन पड़ती है तो उसमें ये लोग कहते हैं कि पी डब्लू डी के द्वारा हम मरम्मत नहीं होने देंगे। अपनी सड़क की तो ये खुद मरम्मत करते नहीं है और हिन्दुस्तान भर में पी डब्लू डी और सी० पी० डब्लू डी की जो भी सड़क होती है उस पर अपनी मोटर गाड़ियां और भारी मोटर गाड़ियां चलाने के लिये तैयार हैं। लेकिन इनके यहां एक फर्लांग भी डिफेंस की जमीन सड़क में आ गई तो ये चाहते नहीं कि इसकी मरम्मत कराई जाय या बराबर वाली सड़क के बराबर कर दिया जाय। यह शिलांग में जहां डिफेंस का डिपो है वहां पर मैंने देखा है कि केवल एक फर्लांग का रास्ता है। डिफेंस मिनिस्ट्री से वहां के गांव के लोग, प्रधान लोग, कई बार फरियाद कर चुके हैं कि पी डब्लू डी ने यह सड़क ले ली है, इसमें एक फर्लांग जो यह पड़ता है इसकी चाहे तो डिफेंस मिनिस्ट्री वाले मरम्मत करा दें, नहीं तो पी डब्लू डी के लोगों को देदें वे मरम्मत कर देंगे। लेकिन जिद है क्योंकि पल्टन के लोग हैं, इनकी जिद हुआ करती है। इनकी जरूरत पड़ती है जब मुल्क पर कोई खतरा आता है तो हम लोग इनके यहां कहने जाते हैं कि आइये मदद कीजिये। लेकिन इतना मैं कह देना चाहता हूं कि किसी मुल्क की हिफाजत अकेले पल्टन नहीं किया करती है, मुल्क की हिफाजत मुल्क की तमाम जनता किया करती है। इसलिये उसकी जरूरतों को नजर अन्दाज करके केवल पल्टन की जमीन के नाम पर गरीब को उजाड़ते जायेंगे और जो लोग राज काज में रहेंगे उन के बेटों को कारखाना खोलने के लिये इजाजत देंगे तो यह आप का बिल बिल्कुल निकम्मा होगा और इस बिल को पेश करके आप केवल इस सदन का समय खराब करेंगे। इतना ही मुझे कहना था।

SHRI J. B. PATNAIK: I am thankful to the hon. members for their observations and I take it that

[Shri J. B Patnaik]

they have accorded general support to the Bill. Some confusion has been created by certain speaches made by hon members regarding defence land in cantonments and land to be brought under restriction as provided for in this Bill. We are not discussing cantonment land which comes under a different Act altogether, that is, the Cantonments Act, of 1924. I assure the House that Government are contemplating a comprehensive Bill to amend the Cantonment Act of 1924 which would be brought before this House as early as possible, may be in the next budget session of Parliament.

But this Bill, as I have said earlier, is an enabling Bill of a very simple nature. I do not understand how some hon. Members have asked for a comprehensive legislation. This legislation for this particular purpose is comprehensive. This Act the Indian Works of Defence Act, 1903, is a comprehensive Act itself. While this Act was being worked over the last so many years, certain deficiencies have been found out. The purpose of this Bill is to remove those deficiencies in the working of this Act.

As I have observed earlier, hon. Members would appreciate that works of defence need a certain amount of safety and security. For that purpose, there should be some restrictions on the constructions around the works of defence or adjacent to the works of defence. For that purpose, this Act is now empowering the Collector, or the officer so empowered, to apply to the Police Commissioners in particular places where they have both police powers and magisterial powers. Some new Police Commissioners posts have been created in certain cities, and there may be such posts created in future. This Act has only taken this fact into account and that is why this amendment has been brought forward. So, I request hon. Members to accept this amendment which is of a very simple and enabling nature.

I shall now come to certain observations made by some hon. Members in this respect. The hon. Member, Shri Mohammad Ismail, made an observation regarding the lands which are illegally trespassed upon. Everybody knows that not only defence land but Government land all over the country is trespassed upon. There are thousands of such cases. They will also remember that scores of cases have been instituted against such trespass by individuals. I would only request hon. Members to use their influence over the people not to trespass upon the land that belongs to Government, either in the Defence Ministry or in any other Ministry.

AN HON. MEMBER: Maruti

SHRI J B. PATNAIK: The ghost of Maruti is still possessing many people's minds, it is still haunting them. This has been comprehensively dealt with in the House, and I do not want to waste the time of the hon. House over. Maruti again.

PROF. MADHU DANDAVATE (Rajapur): The word 'Maruti' has been declared as unparliamentary!

SHRI J. B. PATNAIK: As regards surplus land, Government is thinking of a comprehensive Bill as to how to dispose of surplus land belonging to defence. After this policy is decided upon, I hope it would be to the satisfaction of the hon. Members. For the present, our land policy has not been a stable one. Therefore, the Government is thinking of a comprehensive policy in regard to the land belonging to defence and to dispose of the surplus land thereof.

When that policy comes into operation, the grievances of landless ex-servicemen and the needs of the local bodies and municipalities would be taken into account. Certain specific cases have been mentioned by some

hon. Members Shri Gowda and others. I promise that I shall look to those cases and they would be dealt with fairly. With these words, I commend the Bill to the House.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That the Bill further to amend the Indian Works of Defence Act, 1903, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration".

The motion was adopted.

MR DEPUTY-SEAPKER: We take up clause-by clause consideration.

The question is:

"That clause 2 to 4 stand part of the Bill".

The motion was adopted

Clause 2 to 4 were added to the Bill.

Clause 1 (Short title).

Amendment made.

Page 1, line 4.—

for "1973" *substitute* "1974" (2)

(Shri J. B. Patnaik)

MR. DEPUTY-SPEAKER The question is.

"That clause 1, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 1, as amended, was added to the Bill.

Enacting Formula

Amendment made·

Page 1, line 1.—

for "Twenty-fourth Year"

Substitute—

"Twenty-fifth Year"

(Shri J. B. Patnaik)

MR. DEPUTY-SPEAKER· The question is:

"That the Enacting Formula, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

The Enacting Formula, as amended, was added to the Bill.

The Title was added to the Bill.

SHRI J B PATNAIK. I beg to move

'That the Bill, as amended, be passed"

MR DEPUTY-SPEAKER The question is:

'That the Bill, as amended, be passed."

The motion was adopted

MR DEPUTY-SPEAKFR I am told that the hon Home Minister will be ready with the statement round about 5.30, not 5 00 I am mentioning this so that Members who are interested may know We shall now take up the next business.

---

16 24 hrs.

RESERVE BANK OF INDIA (AMENDMENT) BILL

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRIMATI SUSHILA ROHATGI): I beg to move:

"That the Bill further to amend the Reserve Bank of India Act, 1934, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration."

This Bill seeks to amend certain provisions of the Reserve Bank of India Act, 1934. At this stage, while commending the Bill or consideration, I shall make a mention of only the relatively more important amendments.

One set of amendment is intended to extend the scope of refinance from the Reserve Bank primarily for agricultural operations It is proposed to extend the facility of concessional refinance to apex co-operative Banks in respect of loans given by them to co-operatives formed exclusively for activities allied to agriculture such as poultry farming, pisciculture, etc. There is also a proposal to permit the Reserve Bank finance the development of fisheries through loans from the National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund. Certain pro-